www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 82 | जौनपुर बुधवार, 05 नवम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

तेजप्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का किया ऐलान

बिहार, (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव 225 के रण में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस चुनावी रण में एक और नई पार्टी टक्कर देने को तैयार है। दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी का नाम श्जनशक्ति जनता दलश है और पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। तेज प्रताप यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर चुनाव चिन्ह के साथ अपनी पार्टी का पोस्टर भी जारी कर दिया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर है। तेज प्रताप यादव ने ग हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी का मकसद राज्य में संपूर्ण बदलाव करने के साथ ही एक नई व्यवस्था का निर्माण करना है। जनशक्ति जनता दल के जरिए तेज प्रताप यादव राज्य के संपूर्ण विकास के लिए न सिर्फ संघर्ष करेंगे, बल्कि आगामी चुनावी रण में उतरकर विरोधियों को भी कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का पोस्टर लॉन्च किया है। इस पोस्टर में 5 महापुरुषों महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बीआर अंबेडकर, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें हैं। तेज प्रतार यादव द्वारा नई पार्टी के ऐलान से आरजेडी में खलबली मच गई हैं।

इमामगंज सीट पर दांव पर लगी मांझी की विरासत

बिहार, (एजेंसी)। बिहार की सियासत में गयाजी जिले का इमामगंज हमेशा से अपनी एक विशेष पहचान रखता आया है। इमामगंज सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि यह वो इलाका है, जहां पर जंगल, पहाड़ और ऐतिहासिक विद्रोह की कहानियां गूंजती हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इमामगंज विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इमामगंज विधानसभा सीट से एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा मांझी चुनावी रण में उतरी हैं। दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से रितु प्रिया चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए यहां से अजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के जीतन राम मांझी ने इस सीट से जीत हासिल की थी।

जंगलराज बना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, मोदी-योगी सहित सभी नेताओं ने की ये कोशिश

बिहार, (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव जब शुरु हुआ था, तब यह अनुमान लगाना कठिन था कि इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा।मतदाता किस मुद्दे पर वोट डालेंगे और इसका संभावित असर क्या हो सकता है। लेकिन पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने तक यह साफ दिख रहा है कि तथाकथित जंगलराज बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। संभवतः अब मतदाताओं के सामने यह स्पष्ट विकल्प है कि वे किस पक्ष की ओर वोट डालेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव ने बिहार की चुनावी लड़ाई को लगभग आमने–सामने की लड़ाई में तब्दील कर दिया है जिसे प्रशांत किशोर के मैदान में आने से त्रिकोणीय होने की संभावना जताई जा रही थी। भाजपा ने एक रणनीति के अंतर्गत जंगलराज पर ही अपना फोकस बनाए रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने जनता को लालू राज की याद दिलाने में कोई कमी नहीं रखी। जदयू, लोजपा (आर) और जीतनराम मांझी–उपेंद्र कुशवाहा सहित सभी सहयोगी दलों ने भी इसी मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। एनडीए की इस रणनीति का यह असर हुआ कि बिहार के युवाओं–महिलाओं के बीच यह चर्चा का विषय बन गया कि उन्हें 2005 से पहले का लालू यादव का दौर चाहिए, या 2005 से लेकर अब तक नीतीश राज का दौर चाहिए। मोकामा के दुलारचंद यादव की हत्या ने अनजाने में ही इस मुद्दे को स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा कर दी। लालू यादव के बेहद करीबी रहे दुलारचंद यादव को जातिगत राजनीतिक हिंसा के दौर का प्रतीक माना जाता था। उसकी हत्या ने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू किया जिसका अंतिम परिणाम यह दिखाई पड़ा कि कोई भी अब उस दौर की वापसी नहीं चाहता जहां जाति के नाम पर हिंसा होती हो। जेन जी ने इसी विचार से प्रेरित होकर जातीय हिंसा के दौर को नकार दिया। एक तरफ जहां एनडीए अपने जंगलराज और विकास के मुद्दे को लेकर एकजुट रहा, वहीं महागठबंधन मुद्दों को लेकर भ्रमित दिखा।

भोरे विधानसभा सीट पर एनडीए के लिए अग्निपरीक्षा

बिहार, (एजेंसी)। बिहार के गोपालगंज जिले का भोरे विधानसभा सीट राज्य की राजनीति में एक खास पहचान रखती है। यह सीट गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 1957 में इस सीट का गठन हुआ था। इनमें कटेया, भोरे और विजयीपुर प्रखंड शामिल हैं। यह क्षेत्र न सिर्फ सियासी रूप से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी दिलचस्प है। भोरे विधानसभा क्षेत्र में अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान यहां से सत्ता का संतुलन कई बार बदलता रहा है। इस सीट पर पहले चरण यानी की 06 नवंबर को मतदान होने हैं। इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने 8 बार जीत हासिल की है। इसके साथ ही जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने भी यहां से 2–2 बार जीत हासिल की है। वहीं जेडीयू और जनता पार्टी को एक–एक बार जीत मिली है। साल 2020 के चुनाव में यहां से जेडीयू ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम था। वहीं यहां की राजनीतिक दिशा यत करने में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका है। भोरे सीट पर

अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर जेडीयू ने सुनील कुमार पर भरोसा जताया है। तो वहीं से धनंजय कुमार को टिकट दिया गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में नया और अनोखा प्रयोग करने के साथ ही गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा से थर्ड जेंडर प्रीति किन्नर को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रीति की सामाजिक कार्यों और स्थानीय जुड़ावों के कारण जनता के बीच खास कनेक्शन है। गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला होने के साथ ही आरजेडी का भी यहां पर मजबूत प्रभाव माना जाता है।

हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि भारत की शक्ति, आध्यात्मिकता और पहचान का प्रतीक : किरेन रीजीजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को कहा कि हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि भारत की शक्ति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। वह यहां 'लेखक गांव' में आयोजित 'स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025' में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। रीजीजू ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश से होने के कारण हिमालय से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, ''हिमालय केवल पर्वत नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, आध्यात्मिकता और पहचान का प्रतीक है।'' केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीमा क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गुंजी क्षेत्र में सड़क संपर्क और अवसंरचना के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की सुंदरता इसकी विविधता में निहित है। रीजीजू ने कहा, ''हम भले ही अलग–अलग भाषाएं बोलते हों और अलग परंपराएं निभाते हों, परंतु हमारे मूल्य और दृष्टि हमें एक सूत्र में बांधती है।'' उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की 'लेखक गांव' पहल की सराहना करते हुए इसे भारत के सांस्कृतिक, साहित्यिक और पारिस्थितिक पुनर्जागरण का जीवंत उदाहरण बताया। इस महोत्सव का विषय 'अंतरराष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव' था। निशंक ने इस आयोजन को उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री के स्वप्न को समर्पित किया।

बिहार का विकास केवल एनडीए की गारंटी, कांग्रेस-राजद ने रोकी प्रगति : राजनाथ सिंह

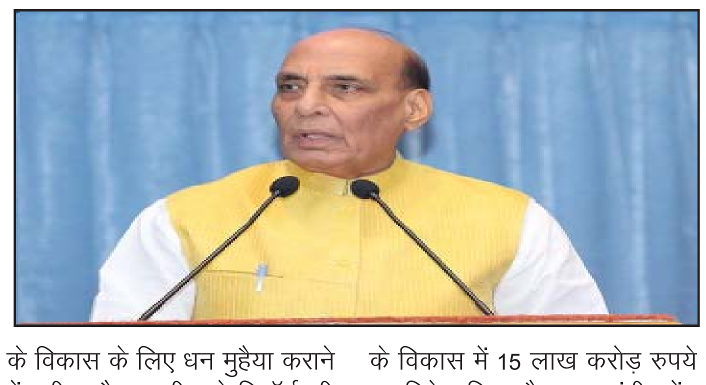

बिहार, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए वह बिहार की प्रगति में बाधा डालती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास ही राज्य के विकास को गति देने की दूरदर्शिता और क्षमता है। राघोपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने विकास पर ध्यान न देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि जब भी वे (कांग्रेस) सत्ता में आते हैं, विकास पर ब्रेक लगा दिया जाता है। अगर किसी में विकास की क्षमता है, तो वह एनडीए है। सिंह ने बिहार के विकास के लिए धन मुहैया कराने में यूपीए और एनडीए के रिकॉर्ड की तुलना करते हुए कहा कि जब यूपीए केंद्र में थी, तब उसने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपये दिए थे। एनडीए के तहत, पिछले 10 वर्षों में, हमने बिहार के विकास में 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक कद पर प्रकाश डालते हुए, सिंह ने मतदाताओं से बिहार में निरंतर प्रगति और स्थिरता के लिए एनडीए का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन का एक दशक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड विकास और सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ष्आज, जब भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो पूरी दुनिया भारत की बात सुनती है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने के समय के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए राजद की आलोचना की। दरभंगा में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए, अपने विशिष्ट उत्साह के साथ, उन्होंने बोलना शुरू किया,।

एलजेपीने बिहार से ज्यादा केंद्र की सत्ता में बनाई भागेदारी, ऐसे हुई थी पार्टी की स्थापना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन ऐसे नेता ने किया था, जिसको राजनीतिक मौसम का वैज्ञानिक माना जाता था। यह नेता और कोई नहीं बल्कि रामविलास पासवान थे। बिहार की सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी की हमेशा सत्ता में भागेदारी रहती है। पार्टी की यह हिस्सेदारी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता में भी मिलती है। जब बिहार की राजनीति के हाल बदले तो रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बना ली। साल 2000 में राम विलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। इससे पहले रामविलास पासवान जनता पार्टी और फिर जनता दल और इसके बाद जनता दल यूनाइडेट का हिस्सा रहे। लेकिन बिहार की सियासत बदली तो रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बना ली। दलितों की राजनीति करने वाले रामविलास पासवान ने साल 1981 में दलिन सेना संगठन की स्थापना की। एलजेपी का गठन सामाजिक न्याय और दलित पीड़ितों की आवाज को उठाने के मकसद से किया गया था। बता दें कि बिहार में दलित समुदाय की आबादी करीब 17 फीसदी है, लेकिन दुसाध जाति का वोट करीब 5 फीसदी है। यह लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 4 सीटें जीती थीं और 4 सीटों के साथ यूपीए का हिस्सा बने। फिर साल 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और 29 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन राज्य में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिल पाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा और अक्तूबर–नवंबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। इस दौरान एलजेपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमटकर रह गई। फिर साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी सिर्फ 3 सीटों पर कब्जा जमा पाई और 2011 में एलजेपी को एक झटका फिर लगा, जब पार्टी के 3 में से 2 विधायक दूसरी पार्टी के साथ चले गए।

चुनाव आयोग करेगा बीएमसी समेत स्थानीय चुनावों की तारीखों का ऐलान

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र चुनाव आयोग मंगलवार शाम 4 बजे बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे इस संबंध में मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विपक्ष ने चुनाव स्थगित करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि 1 जुलाई की मतदाता सूची में कई अनियमितताएँ हैं, जिनमें नकली और फर्जी नाम भी शामिल हैं। इस संबंध में, शिवसेना (यूबीटी) ने कहा है कि वह सबूतों के साथ अदालत जाने की योजना बना रही है। हालाँकि, चुनाव अधिकारियों ने कहा कि एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, अदालत के लिए हस्तक्षेप करना मुश्किल होगा। 3 नवंबर को, वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वाल्से पाटिल ने महाराष्ट्र में लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानीय निकायों और नगर निगमों के चुनावों की संभावित तारीखों की घोषणा करके खलबली मचा दी, जबकि चुनाव आयोग ने अभी तक

औपचारिक रूप से कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के चुनाव 15 दिसंबर को होने की संभावना है, जबकि नगर निगम के चुनाव 15 जनवरी को हो सकते हैं। वाल्से पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अंतिम समय सीमा 31 जनवरी, 2026 तय की है। वाल्से पाटिल ने एक वायरल वीडियो में कहा कि जिला परिषद चुनाव 15 दिसंबर और नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को हो सकते हैं। स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी।

ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद बंगाल में एसआईआर शुरू

कोलकाता, (संवाददाता)। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का खुलकर विरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की है कि वह अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए मंगलवार (4 नवंबर) को कोलकाता में एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण

प्रक्रिया का दूसरा चरण पश्चिम बंगाल सहित उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं। एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से एक दिन पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने आखिरी क्षणों की तैयारी के तहत सोमवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के एसआईआर के लिए घर–घर जाने के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। बीएलओ और अन्य अधिकारियों को बिना किसी डर के मंगलवार से घर–घर जाकर सर्वेक्षण करने और इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता का तीन दिवसीय प्रचार अभियान शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए के कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए पटना पहुंची हैं। अगले तीन दिनों में उनकी 12 और जनसभाएं आयोजित होंगी। एक भाजपा नेता ने इसकी पुष्टि की। आप मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है, ष्अगले तीन दिनों तक, मुख्यमंत्री पूरे राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, सहयोगी पार्टियों के नेता, साथ ही पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी होंगे। जनसभाओं के अलावा, मुख्यमंत्री रोड शो में भी हिस्सा लेंगी। ज्यादा जानें संपादकीय लेखन सेवा बजट विश्लेषण रिपोर्ट हिंदी पत्रकारिता कार्यशाला विविध लेख

बॉलीवुड समाचार अलर्ट समाचार सदस्यता युवा समाचार मंच यात्रा पैकेज बिहार क्षेत्रीय समाचार ऐप विदेश समाचार यह मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार के लिए बिहार का तीसरा दौरा होगा। इस अति–व्यस्त दौरे में सीएम रेखा गुप्ता तीन दिनों में 12 से 15 निर्वाचन क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करेंगी, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। 7 नवंबर को भव्य आयोजन तीन दिवसीय अभियान के दौरान, मुख्यमंत्री 4 नवंबर को सीवान, बरहरिया, बैकुंठपुर और आस–पास के इलाकों सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां, जनसभाएं और रोड शो करेंगी। 5 नवंबर को, उनका अभियान गौरा बौराम, अरवल, गया शहर और औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगा। 6 नवंबर को, वह भागलपुर, वारिसलीगंज, हिसुआ और दिनारा निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री के 6 नवंबर की शाम को नई दिल्ली लौटने की उम्मीद है। अग्रणी तकनीकों से बदलेगी खेती की तस्वीर मुख्यमंत्री के बिहार शेड्यूल की घोषणा उस दिन की गई जब भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने दिल्ली में पार्टी के महासचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले एक चुनावी रैली के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके 15 साल के शासन को बिहार में कानून–व्यवस्था की कमी और उद्योगों और चीनी मिलों के बंद होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। ज्यादा जानें आवारा पशु कल्याण दान कविता संग्रह कविता संग्रह प्रकाशन युवा विशेष सामग्री समाचार सदस्यता है।

संपादकीय

डॉनल्ड ट्रंप की कार्यशैली

ट्रंप के लिए गोल–पोस्ट बदल लेना आम बात है। रूस से तेल खरीदारी रुकवाने तक वे सीमित रहेंगे, यह सोचना भूल है। ब्रिक्स़ से अलगाव और भारतीय पूंजी का अमेरिका में निवेश करवाना उनकी अगली प्राथमिकताएं हो सकती हैं। भारत सरकार जिसे पहले देश की ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक अपना संप्रभु निर्णय कहती थी, उस मामले में झुकने का संकेत देकर उसने सारी दुनिया में बहुत गलत संदेश भेजा है। ताजा घटनाओं से अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा सच होता दिखा है कि इस वर्ष के अंत तक रूस से कच्चे तेल की खरीदारी रोक देने का गुपचुप आश्वासन उन्हें दिया गया। इन खबरों के बाद चर्चा फिर गर्म है कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर दोनों देश सहमति की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक बताया गया है कि अब समझौते का प्रारूप लिखा जा रहा है। प्रस्तावित समझौते में कृषि एवं डेयरी क्षेत्रों को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने की ट्रंप प्रशासन की मांग पर भारत कहां तक झुकेगा, यह अभी साफ नहीं है। मगर वह सिर्फ एक मुद्दा है। डॉनल्ड ट्रंप की कार्यशैली से जाहिर है कि ट्रेड डील उनके लिए सिर्फ व्यापार घाटा पाटने का जरिया नहीं है। बल्कि इसे उन्होंने अमेरिका के व्यापक भू–राजनीतिक हितों को साधने का औजार बना रखा है। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के संदर्भ में उनके दावे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। फिलहाल एक विज्ञापन को आधार बना कर जिस तरह उन्होंने कनाडा से व्यापार वार्ता तोड़ दी, उससे यही संकेत मिला है कि ट्रंप के लिए गोल–पोस्ट बदल लेना आम बात है। यानी वे रूस से तेल खरीदारी रुकवाने तक सीमित रहेंगे, यह सोचना भूल है। ट्रंप ने ब्रिक्स़ को निशाने पर ले रखा है, जिससे भारत को अलग करवाना उनका अगला मकसद बन सकता है। फिर भारतीय पूंजी का अमेरिका में निवेश करवाना उनकी आगे की प्राथमिकता हो सकती है। व्यापार समझौतों में उन्होंने ऐसा करने के लिए कई देशों को मजबूर किया है। यह साफ है कि जो देश कमजोरी दिखाते हैं, उनके ऊपर और चढ़ते जाना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। इसीलिए ताजा घटनाक्रम भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। झुक कर किया गया ट्रेड डील भारत की स्वायत्त पहचान पर कलंक लगाएगा, जिसका खराब असर अन्य द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र अभी से भी संभल जाए।

मैराथन मैन अनिल अंबानी कैसे कारोबारी दौड़ में पिछड़ कर कानूनी ट्रैक में फंस गये?

नीरज

कभी भारत की कॉर्पोरेट दुनिया में "सफलता का प्रतीक" कहे जाने वाले अनिल अंबानी आज उस दौर में खड़े हैं जहाँ उनका नाम किसी बिजनेस मॉडल से नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से जुड़ा दिखाई देता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अनिल अंबानी की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की गयी है जिसमें मुंबई के पाली हिल स्थित उनका घर और रिलायंस समूह की कई प्रतिष्ठित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। यह सिर्फ एक कारोबारी पर कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक संदेश है। देखा जाये तो यह मामला सिर्फ एक उद्योगपति के पतन की कहानी नहीं, बल्कि उस तंत्र की परीक्षा है जो यह दिखा रहा है कि धान और प्रभाव अब कानून से ऊपर नहीं हैं। ईडी की जांच के मुताबिक, अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियोंकृ रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर–कॉम), रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने पिछले एक दशक में सरकारी और बैंकिंग संस्थानों से हजारों करोड़ रुपये जुटाए। आरोप है कि इनमें से बड़ी रकम समूह की अन्य कंपनियों या संबद्ध इकाइयों में स्थानांतरित की गई और कुछ धनराशि विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए भेजी गई। ईडी ने यह भी दावा किया है कि "एक कंपनी से लिए गए ऋण का उपयोग दूसरी कंपनी के ऋण चुकाने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने में किया गया", जो सीधे तौर पर ऋण की शर्तों का उल्लंघन था। यह तथाकथित "एवरग्रीनिंग मॉडल", जहाँ पुराने ऋण को नए ऋण से ढका जाता है, भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पुरानी बीमारी रही है। हम आपको याद दिला दें कि अनिल अंबानी का उदय भारतीय उदारीकरण के स्वर्णकाल का प्रतीक था। उनके प्रोजेक्ट्सकृ टेलीकॉम से लेकर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर तक, 90 के दशक की नई आर्थिक नीतियों के पोस्टर चाइल्ड थे। परंतु वही पूंजीवाद, जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए था, धीरे–धीरे "कॉर्पोरेट कार्टेल" में बदल गया। रिलायंस कम्युनिकेशंस की गिरावट से शुरू हुआ वित्तीय संकट अब कानूनी संकट में तब्दील हो चुका है। पहले यह मामला "बाजार की असफलता" कहा जाता था, अब इसे "वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग" के रूप में देखा जा रहा है। जब किसी समय बैंकों ने 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इस समूह को ऋण स्वरूप दी थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि 19,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि एनपीए बन जाएगी और उसके बाद जांच एजेंसियों को धनशोधन का पैटर्न मिलेगा। देखा जाये तो ईडी की ताजा कार्रवाई को महज एक उद्योगपति के खिलाफ कानूनी कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारत की आर्थिक पारदर्शिता के उस नए युग की घोषणा है जिसमें "ब्रांड वैल्यू" से ज़्यादा "सत्यापन मूल्य" मायने रखता है। हाल के वर्षों में, प्रवर्तन एजेंसियों पर राजनीतिक पक्षधरता के आरोप लगते रहे हैं। परंतु जब ईडी जैसे संस्थान एक ऐसे उद्योगपति पर कार्रवाई करते हैं, जो कभी भारत की कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा का चेहरा था, तो यह संकेत देता है कि आर्थिक अपराधा की रेखा अब राजनीतिक समीकरणों से परे खींची जा रही है। अनिल अंबानी का मामला यह दिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अगर उसने बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग किया, तो जवाबदेही तय होगी। देखा जाये तो यह कार्रवाई उस दौर में हुई है जब भारत की आर्थिक व्यवस्था में जनता का भरोसा दोतरफा दबाव में है। एक ओर कॉर्पोरेट घोटालों की गूंज, दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न। ऐसे में जब ईडी सैंकड़ों पन्नों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस संपत्ति कुर्क करती है, तो यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना है। हालांकि यह भी सच है कि कई मामलों में ईडी की जांच वर्षों तक अदालतों में उलझ जाती है और ठोस दंडात्मक परिणाम सामने नहीं आते। इसलिए यह आवश्यक है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और न्यायोचित रहे क्योंकि यदि न्याय देर से मिलेगा, तो संदेश खो जाएगा। अनिल अंबानी केस से निकले व्यापक सबक को देखें तो भारत के निजी क्षेत्र में ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया और उससे जुड़ी जवाबदेही पर यह मामला बड़ा सवाल उठाता है। बैंकिंग सेक्टर में केवल "क्रेडिट स्कोर" नहीं, बल्कि "कंट्रोल स्कोर" की भी निगरानी आवश्यक है, यानी, पैसा कहाँ और कैसे जा रहा है, इसका ट्रैक पारदर्शी होना चाहिए। देखा जाये तो लंबे समय तक भारत में उद्योग और सत्ता के रिश्ते इतने गहरे रहे कि जवाबदेही धुंधली पड़ गई है। हालांकि यह मामला यह संदेश देता है कि सत्ता से समीपता अब सुरक्षा कवच नहीं है। देखा जाये तो अनिल अंबानी की कहानी एक व्यक्ति की असफलता भर नहीं है, बल्कि उस प्रणाली का आईना है जिसने दशकों तक "कर्ज के सहारे साम्राज्य" खड़ा करने की अनुमति दी। अब जब वही व्यवस्था कठोर जांच के घेरे में है, तो यह न केवल एक उद्योगपति का पतन है, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट संस्कृति के आत्ममंथन का क्षण भी है। यह कार्रवाई आने वाले समय के लिए संकेत देती है कि भारत का आर्थिक नियमन अब "कर्ज वितरण" की जगह "कर्ज अनुशासन" पर आधारित होगा। और जो भी व्यक्ति या संस्था

सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करेगी, वह कानून की पकड़ से नहीं बच पाएगी, भले ही उसका नाम अंबानी ही क्यों न हो। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई एक ऐतिहासिक मोड़ है क्योंकि यह केवल एक नाम पर नहीं, बल्कि उस सोच पर प्रहार है जो मानती थी कि प्रभावशाली लोग जवाबदेही से मुक्त हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में यह दिन इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि धन का आकार चाहे जितना भी बड़ा हो, कानून की रेखा उसके ऊपर नहीं खींची जा सकती। यह संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शासनतंत्र के लिए है कि "कानून की दिशा वही है जहाँ जवाबदेही जीवित है। बहरहाल, कभी "मैराथन मैन" कहे जाने वाले अनिल अंबानी, जो 40 की उम्र के बाद अपने अनुशासन और फिटनेस से प्रेरणा का प्रतीक बने थे, आज आर्थिक और कानूनी लड़ाई की दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वह केवल कारोबारी जगत की शख्सियत नहीं थे, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उनका प्रभाव माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले समर्थक माने जाने वाले अनिल अंबानी ने 2014 के बाद के दौर में खुद को "नए भारत के औद्योगिक चेहरे" के रूप में प्रस्तुत किया था। मगर आज तस्वीर उलट चुकी हैकृ सत्ता से नजदीकी भी उन्हें न तो वित्तीय पतन से बचा पाई, न ही ईडी की सख्ती से। यह समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्थायित्व सत्ता से नहीं, बल्कि सत्य और पारदर्शिता से आता है। दौड़ चाहे फिटनेस की हो या वित्त की, अगर नियम टूटते हैं, तो मंजिल तक पहुँचने वाला भी रास्ता खो देता है।

भारतीय महिला क्रिकेट– नई उड़ान, नई संभावना को सलाम

ललित गर्ग

2 नवंबर 2025 का रविवार भारतीय खेल जगत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। यह वह दिन था जब नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मैदान न केवल एक विश्व कप का साक्षी बना, बल्कि भारतीय महिला शक्ति की अजेय प्रतिभा और जज्बे का भी प्रमाण देखा। शेफाली

वर्मा ने 87 रन की पारी खेल कर विश्वकप को भारत के नाम कराने में अमूल्य योगदान दिया। शेफाली की यह पारी आत्मविश्वास से भरी होने के साथ–साथ सनसनीखेज पारी रही। इसी के साथ स्मृति मंधाना ने अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए भारत के लिये सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उनकी टाइमिंग एवं कंवर ड्राइव ने सबका दिल जीत लिया। वैसे टीम का हर खिलाड़ी इस आश्चर्यकारी जीत के लिये बधाई का पात्र है। निश्चित ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अपने नाम कर ऐसा इतिहास रचा, जो न केवल खेल का अध्याय है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और नारी सशक्तिकरण की प्रेरक गाथा भी है। विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की चर्चा दुनिया के हर कोने में हो रही है। यह जीत केवल एक ट्रॉफी भर नहीं, बल्कि उस नारी शक्ति का उद्घोष है जो वर्षों से अपने अस्तित्व को साबित करने में लगी थी। भारतीय बेटियों ने मैदान में यह दिखा दिया कि अब "खेल" सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रहा, यह वह मंच है जहां नारी की प्रतिभा, रणनीति, धैर्य और आत्मविश्वास अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि "यह केवल क्रिकेट की जीत नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति, परिश्रम और आत्मविश्वास की जीत है।" सच भी यही है कि यह विजय भारत की नई महिला चेतना का प्रतीक है, वह चेतना जो अब हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। अब भारतीय महिलाओं को हाशिया नहीं, पूरा पृष्ठ चाहिए और यह बात उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करके साबित किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारत और दक्षिण–अफ्रीका का फाइनल विश्व कप मैच सदा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई है। हरमनप्रीत की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम ने यह यादगार जीत हासिल की है। इससे पहले मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम 2005 और 2017 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन यहां आकर ट्रॉफी हाथ से फिसल गई थी। भारतीय महिला टीम ने टॉस हारने के बाद भी बल्लेबाजी के लिए उतरी और 298 रन बनाए। साउथ अफ्रीक की टीम इस आंकड़े को छू नहीं पाई, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर 47 साल के इंतजार को खत्म किया। इस महान सफलता के पीछे आईसीसी अध्यक्ष जय शाह की दूरदर्शी नीतियों और नेतृत्व का भी बड़ा योगदान है। उनके कार्यकाल में महिला क्रिकेट को वह सम्मान और अवसर मिले जिसकी वह वर्षों से हकदार थी। जय शाह ने न केवल संरचनात्मक सुधार किए बल्कि महिला क्रिकेट के लिए आधारभूत ढांचे, सुविधाओं और प्रोत्साहन योजनाओं को नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब नेतृत्व में दृष्टि होती है, तो इतिहास बदलता है। इस विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल से दुनिया को चकित किया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिस साहस और सूझबूझ से टीम का नेतृत्व किया, वह प्रेरणा का विषय है। उनके बल्ले से निकले हर रन ने नारी शक्ति की धुन गाई। स्मृति मंधाना की क्लासिकल बल्लेबाजी ने विपक्षी गेंदबाजों को बेहाल कर दिया, जबकि युवा खिलाड़ी शैफाली वर्मा की आक्रामकता ने नई पीढ़ी की ऊर्जा को स्वर दिया। गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर और पूजा वस्त्राकर की सटीक लाइन–लेंथ ने टीम को हर मुश्किल समय में संभाला, वहीं स्पिनर दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई गेंदों से विरोधियों के हौसले पस्त किए। इस टूर्नामेंट में भारत की फील्डिंग और फिटनेस भी अप्रतिम रही, जो यह दर्शाती है कि अब भारतीय महिला क्रिकेट केवल तकनीक नहीं, बल्कि रणनीति और समर्पण के सर्वोच्च मानकों पर खड़ी है। महिला क्रिकेट खिलाड़ी नवीन क्षमताओं की नई उड़ान भरते हुए हर मन की मुराद पूरी कर रही है। यह जीत केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय खेल संस्कृति में परिवर्तन की दिशा का प्रतीक है। आज भारत की बेटियां छोटे कस्बों और गाँवों से निकलकर विश्व मंच पर चमक रही हैं। यह उस सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है जिसमें परिवार, समाज और सरकार ने नारी खेल प्रतिभा को अवसर देना शुरू किया है। महिला विश्व कप 2025 ने यह सिद्ध कर दिया कि अब भारत में खेल सिर्फ "मैदान" तक सीमित नहीं, यह राष्ट्रीय चेतना और गौरव का हिस्सा बन चुका है। यह नारी स्वाभिमान, श्रम और संघर्ष की कहानी है। क्रिकेट अब केवल पुरुषों की लोकप्रियता का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की असाधारण योग्यता का उत्सव बन गया है। भारत की यह जीत उस भविष्य की ओर इशारा करती है जहाँ खेल, लिंग भेद से परे, केवल प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर सम्मान पाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह ऐतिहासिक विजय केवल कप जीतने की कहानी नहीं है, यह उस भारत की घोषणा है जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का साहस रखता है। यह जीत हर उस लड़की की प्रेरणा है जो गली के मैदान में क्रिकेट बैट थामे सपना देखती है कि एक दिन वह भी भारत के लिए खेलेगी। यह स्वर्णिम विजय हमें यह संदेश देती है कि भारत की नारी अब हर क्षेत्र में "खेल बदलने" के लिए तैयार है। जय शाह जैसे सक्षम नेतृत्व और खिलाड़ियों की प्रतिभा से सुसज्जित यह टीम आने वाले समय में विश्व क्रिकेट का नया अध्याय लिखेगी, जहाँ हर शॉट में आत्मविश्वास होगा, हर गेंद में संकल्प, और हर जीत में भारत की बेटियों की दमकती मुस्कान। भारत की बेटियाँ अब सिर्फ खेल नहीं रही हैं बल्कि वे इतिहास रच रही हैं। देश पर छा रहे अनेकानेक उजालों के बीच महिला विश्व कप 2025 रूपी उजाला देशवासियों को प्रसन्नता का प्रकाश दे गया। संदेश दे गया कि देश का एक भी व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने की ठान ले तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। विश्व को बौना बना सकता है। पूरे देश के निवासियों का सिर ऊंचा कर सकता है। महिलाओं की इस करिश्माई उपलब्धि के बाद अखबारों के शीर्ष में यह समाचार छपा और सबको लगा कि शब्द उन पृष्ठों से बाहर निकलकर नाच रहे हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खिलाड़ीपन के लम्बे रन–अप को पल–पल जीया है। इस दौरान बहुत कुछ पीया है तभी वे विश्व विजेता बनी। वरना यहां तक पहुंचते–पहुंचते कईयों के घुटने घिस जाते हैं। एक बूंद अमृत पीने के लिए समुद्र पीना पड़ता है। सम्मान, पदवी, उपाधियां, अलंकरण बहुतों को मिलते हैं पर सही सीने पर सही तमगा और सही नाम के आगे सही सम्बोधन कभी–कभी लगता है। जैसा महिला विश्व कप 2025 की भारतीय महिला खिलाड़ियों के सीनों पर लगा है। जब भी कोई अर्जुन धनुष उठाता है, निशाना बांधता है तो करोड़ों के मन में एक संकल्प, एक एकाग्रता का भाव जाग उठता है और कई अर्जुन पैदा होते हैं। अपने देश में हर बल्ला उठाने वाला अपने को गावस्कर, तेंगुलकर विराट कोहली, रोहित समझता है, हर बॉल पकड़ने वाला अपने को कपिल–अर्शदीप, बुमराह समझता है। हॉकी की स्टिक पकड़ने वाला हर खिलाड़ी अपने को ध्यानचंद, हर टेनिस का रेकेट पकड़ने वाला अपने को रामानाथन कृष्णन समझता है। और भी कई नाम हैं, मिल्खा सिंह, पी.टी. उषा, प्रकाश पादुकोन, गीत सेठी, जो माप बन गये हैं खेलों की ऊंचाई के। आज शेफाली हो स्मृति या फिर जेमिमा हो या दीप्ति आज माप बन गयी है और जो माप बन जाता है

पीके ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया

हरिशंकर व्यास

बिहार विधानसभा का चुनाव एक तरफ, जहां जातियों के आधार पर बंटा हुआ दिख रही है वही दूसरी ओर प्रबंधन और प्रचार पर टिका हुआ भी है। जन सुराज पार्टी बना कर राजनीति में उतरे चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी प्रशांत किशोर ने बिहार की पार्टियों और नेताओं को दिखाया कि कैसे प्रबंधन के जरिए, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कम समय में लोगों की सोच को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने प्रबंधन और प्रचार के जरिए बिहार के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। चुनाव नतीजा क्या होगा, वे कितनी सीटें जीतेंगे, उन्हें कितना वोट मिलेगा यह अलग बात है लेकिन बिना मजबूत जातीय आधार के या किसी टूलकिट की मदद से कोई आंदोलन खड़ा किए बगैर उन्होंने लोगों की सोच और राजनीतिक चर्चाओं में अपनी जगह बनाई। उन्होंने बिहार के मुद्दे उठाए और दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार चुनाव में इनकी बात हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन को लेकर चर्चा हुई। जब प्रशांत किशोर के उठाए मुद्दों पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार घिरने लगी तो जातीय, सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दों के साथ साथ सरकारी फंड से चुनाव चुनाव प्रबंधन का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी, जिसे मुफ्त की रेवड़ी कहते थे वह बिहार जैसे गरीब राज्य में ऐसे बंटी जैसे और कहीं नहीं बंटी। चुनाव से पहले सरकार ने खजाना खोल दिया। महिलाओं के खाते में 10–10 हजार रुपए भेजे गए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को चार सौ से बढ़ा कर 11 सौ रुपया महीना कर दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। किसी समूह को 25–25 हजार रुपए टैबलेट खरीदने के लिए दिए गए तो किसी समूह को 10–10 हजार रुपए स्मार्टफोन के लिए दिए गए। सरकार की योजना में सहयोग देने के लिए नियुक्त किए गए हर समूह का मानदेय दोगुना कर दिया। पत्रकारों की पेंशन भी छह से बढ़ा कर 15 हजार रुपए कर दी गई। कोई 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं सरकार ने चुनाव से दो महीने पहले घोषित कर दी। बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। करीब नौ महीने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन तब भी सत्ता उनके हाथ में थी। उधर 11 साल से ज्यादा समय से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। तभी बिहार की समस्याओं को लेकर जनता के मन में दोनों को लेकर सवाल हैं। यह सही है कि नीतीश को उखाड़ फेंकने वाला गुस्सा नहीं है लेकिन मतदाता के मन में थकान और ऊब जरूर है, जिसे नकद पैसे या मुफ्त की वस्तुएं और सेवाएं बांट कर दूर किया जा रहा है। मुफ्त की सेवाओं और वस्तुओं के सहारे सत्ता विरोध की भावना को कम किया गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर भी चुनाव प्रबंधन का ही हिस्सा था। चुनाव आयोग कुछ भी कहे लेकिन 69 लाख लोगों का नाम कटना मामूली नहीं है। इसमें ज्यादातर नाम ठीक तरीके से कटे हो सकते हैं लेकिन इसके सहारे यह मैसेज बनवाया गया कि सरकार घुसपैठियों को बरदाश्त नहीं करेगी और उनकी पहचान करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं ताकि वे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले सकें और सरकार चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं रहे। सरकार में होने के कई और लाभ सत्तारूढ़ दल या गठबंधन को मिलते हैं। अधिकारियों की पोस्टिंग से लेकर सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों की नाराजगी दूर की जाती है। यह काम सरकार ने किया है। चुनाव से पहले एक एक करके सारे आयोग और निगमों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की गई। उसके सहारे भी सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के नेताओं की नाराजगी दूर की गई। जातीय समीकरण को साधा गया। इसके बाद जब चुनाव आया तो मीडिया, सोशल मीडिया के बंदोबस्तों के साथ साथ प्रधानमंत्री सहित बड़े बड़े नेताओं के प्रचार की कारपेट बॉम्बिंग, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रबंधन, पैसे और साधनों के सहारे चुनाव के प्रबंधन का काम चल रहा है।

भाजपा ने चुनावों से पहले सांस्कृतिक अंधभक्ति की नींव रखी

आशीष विश्वास

बांग्लादेश की बात करें तो यह बहुत बाद में आया। समस्या यह थी कि श्री सरमा और उनके जैसे लोग स्वतंत्रता आंदोलन या बंगाल या अन्य जगहों पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश–विरोधी संघर्षों से वाकिफ नहीं थे, यही उनके निरर्थक तर्कों की व्याख्या करता है। हालांकि, बंगाल कांग्रेस के हलकों का मानना है कि सरमा श्री गोगोई के तर्कों के आगे खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। जाहिर है, अगर राजनीतिक नेता जिद करें, तो श्कविगुरुश रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कुछ गीत विशेष अवसरों को छोड़कर नहीं गाए जा सकते। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने राज्य पुलिस को एक कांग्रेस नेता के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसने कुछ दिन पहले राज्य के श्रीभूमि (करीमगंज) जिले में एक पार्टी समारोह में श्आमार सोनार बांग्लाश गाने का श्पापश किया था। अपने फैसले की व्याख्या करते हुए, श्री सरमा ने कहा कि गायक को पता होना चाहिए था कि वह असल में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रहा था! भारतीय धरती पर एक सभा में इसे गाना राज्य और देश दोनों का अपमान था। श्री सरमा के इस ऐलान से पहले ही इस तरह के मुद्दों पर विवाद खड़ा हो गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तल्ख रिश्तों के अलावा, ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि बांग्लादेश में सक्रिय इस्लामी चरमपंथी एक स्वतंत्र मुस्लिम गणराज्य बंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री शर्मा ने कहा कि चूंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक – पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसे बांग्लादेशी श्मियांश मुसलमानों – के समर्थन के लिए जानी जाती है, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता असम में बांग्लादेशी राष्ट्रगान गाने पर आपत्ति नहीं करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की खुफिया एजेंसियां इस्लामी चरमपंथियों की एक बड़े श्स्वतंत्रश इस्लामी बंगाल बनाने की दीर्घकालिक योजनाओं से आम तौर पर वाकिफ थीं। उन्हें वर्तमान में तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। भारत सरकार के हलकों में ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन पिछले साल 8 अगस्त को अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश सरकार के प्रमुख के रूप में बांग्लादेश पर अप्रत्याशित कब्जा करने से पूर्वोत्तर की स्थिति में काफी बदलाव आया। अस्थायी मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए, डॉ. यूनुस ने पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका के साथ सांठगांठ करके भारत सरकार की सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। उन्होंने बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश की और चीन और पाकिस्तान से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने भारत के साथ व्यापार और व्यवसाय की मात्रा कम कर दी, जबकि इस्लामी देशों के साथ संपर्क बढ़ाए। स्वाभाविक रूप से, भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नए रुझानों पर ध्यान देना पड़ा। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि इसी संदर्भ में श्री सरमा ने यह बात कही थी। भाजपा विरोधी दल मुख्यमंत्री के तर्क से कतई सहमत नहीं थे। सही हो या गलत, सरमा ने एक कट्टर मुस्लिम विरोधी और कट्टर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है। राज्य कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के खिलाफ राष्ट्रीय

आंदोलन के दौरान, टैगोर ने यह गीत लिखा था, जो बंगालियों और यहां तक कि दुनिया भर के कई भारतीयों के बीच एक शक्तिशाली भावनात्मक एकीकरण का सूत्रधार बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गीत को न गाने का कोई ठोस कारण नहीं हो सकता। बांग्लादेश की बात करें तो यह बहुत बाद में आया। समस्या यह थी कि श्री सरमा और उनके जैसे लोग स्वतंत्रता आंदोलन या बंगाल या अन्य जगहों पर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रिटिश–विरोधी संघर्षों से वाकिफ नहीं थे, यही उनके निरर्थक तर्कों की व्याख्या करता है। हालांकि, बंगाल कांग्रेस के हलकों का मानना है कि सरमा श्री गोगोई के तर्कों के आगे खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी श्आमार सोनार बांग्लाश गीत को लेकर एक गलती में शामिल रही थी। इसके अलावा, एक टीएमसी मंत्री का हाल असम के मुख्यमंत्री से भी कहीं ज़्यादा बुरा हुआ, जब उन्होंने बांग्लादेश में ही एक आधिकारिक समारोह में श्आमार सोनार बांग्लाश गाने की कोशिश की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बांग्लादेश यात्रा पर संस्कृति मंत्री और एक गायक, श्री इंद्रनील सेन को भी साथ ले गई थीं। कुछ हद तक भावुक होकर, श्री सेन, जिनका परिवार बांग्लादेश से आया था, अपने दर्शकों से कभी–कभार बातचीत करते हुए भी, अचानक श्आमार सोनार बांग्लाश की कुछ पंक्तियां गाने लगे थे। इसके तुरंत बाद दर्शकों ने विरोध जताया। लोग खड़े हो गए और सेन के गीत को बीच में ही रोक दिया और बताया कि श्आमार सोनार बांग्लाश उनका राष्ट्रगान है। वे किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना किसी गंभीरता के, उस गीत को यूं ही गाने की इजाजत नहीं दे सकते। धिक्कार पाकर, निराश सेन ने गाना बंद कर दिया और बैठ गए। पश्चिम बंगाल से आए गणमान्य लोगों के साथ–साथ उन्होंने भी सबक सीख लिया था।

वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन की दमदार उपस्थिति, लंदन में झलकेगा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव

लखनऊ, (संवाददाता)। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 4 से 6 नवम्बर 2025 तक एक्सेल में आयोजित होने जा रहे प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट (डब्ल्यूटीएम) 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। विश्वभर के पर्यटन विशेषज्ञों, निवेशकों और नीति–निर्माताओं की मौजूदगी वाले इस वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश अपने विविध पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और निवेश की अपार संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करेगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, लंदन में उत्तर प्रदेश पर्यटन के स्टॉल पर भारत की इत्र नगरी कन्नौज की पहचान बने सुगंधित उत्पादों, प्रदेश के स्पिरिचुअल ट्रायंगल प्रयागराज, अयोध्या और काशी की आस्था–यात्रा, यूनेस्को विश्व धरोहर ताजमहल की अद्भुत भव्यता, बौद्ध सर्किट से जुड़े तीर्थस्थलों की ऐतिहासिक महत्ता और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के दर्शन जैसे आकर्षक थीम प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय यह वैश्विक आयोजन पर्यटन उद्योग के विशेषज्ञों, बी2बी मीटिंग्स, साझेदारी के अवसरों, नवाचार, युवा पेशेवरों तथा समावेशी पर्यटन की अवधारणा पर केंद्रित रहेगा। इस अवसर पर पर्यटन प्रोत्साहन से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित होंगी, जिनसे उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक सशक्त, सुरक्षित और पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।जयवीर सिंह ने कहा कि लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन अपने समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव की झलक दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। राज्य के पर्यटन स्टॉल का विशेष आकर्षण कन्नौज की इत्र विरासत और पारंपरिक शिल्पकला होगी। प्रयागराज, अयोध्या और काशी को जोड़ने वाले स्पिरिचुअल ट्रायंगल को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे देश–विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक राज्य की इस आस्था यात्रा से और अधिक जुड़ सकेंगे।उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल और विश्व के सात आश्चर्यों में से एक है, को भी इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों से जुड़े छह पवित्र स्थलकृ सारनाथ, कुशीनगर, संकिसा, कपिलवस्तु, कौशांबी और श्रावस्तीकृ राज्य को बुद्ध भूमि का गौरव प्रदान करते हैं। इन सभी स्थलों को जोड़ने वाला बौद्ध सर्किट अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 'बोधि यात्रा' का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरती पर पहुंचते हैं।मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निरंतर अंतरराष्ट्रीय मंचों, व्यापार मेलों और ट्रैवल मार्केट्स के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक विविधता और पर्यटन क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, लंदन जैसे आयोजन न केवल पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न आयामों को एक मंच पर लाते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सहभागिता के माध्यम से विश्व पर्यटन के नए युग की मजबूत नींव रखने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।लंदन में होने जा रहा यह आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।

बीबीएयू के प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा को 'इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड' से सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) लखनऊ के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. नवीन कुमार अरोड़ा को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित 'इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रकाशन समूह 'स्प्रिंगर नेचर' (चतपदहमत छंजनतम) द्वारा प्रदान किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय शोध जगत में अपनी उच्च विश्वसनीयता और वैज्ञानिक योगदान के लिए जाना जाता है।प्रो. अरोड़ा वर्तमान में 'एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी' नामक अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में कार्यरत हैं। यह पत्रिका पर्यावरणीय स्थिरता, सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर वैश्विक स्तर

पर वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है।स्प्रिंगर नेचर द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई इस पत्रिका ने 2024 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय इम्पैक्ट फैक्टर प्राप्त किया है, जो किसी भी शोध पत्रिका के वैश्विक प्रभाव और गुणवत्ता का सूचक होता है। केवल सात वर्षों के भीतर इस जर्नल ने अंतरराष्ट्रीय शोध समुदाय में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। यह उपलब्धि संपादकीय टीम के सतत प्रयासों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्ट संपादन गुणवत्ता का परिणाम है।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ में आज से शुरू हुआ 'यातायात माह,सड़क सुरक्षा माह' अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज से "यातायात माह ६ सड़क सुरक्षा माह" का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था ने हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, ट्रैफिक कर्मियों तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया गया।अभियान के अंतर्गत पूरे नवंबर माह में पुलिस द्वारा विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें यातायात नियमों पर कार्यशालाएं, रैलियां, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं, स्कूल–कॉलेजों में विशेष सत्र, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम शामिल रहेंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को यह संदेश दिया जाएगा कि सुरक्षित यात्रा केवल नियमों के पालन से ही संभव है।संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना, नशे की हालत में वाहन संचालन से परहेज, मोबाइल फोन का प्रयोग न करना और पैदल यात्रियों के अधिकारों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।पुलिस विभाग ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान जहां लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा,।

अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

लखनऊ, (संवाददाता)।राजधानी लखनऊ में बीती रात सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के गंगानगर अमौसी के पास एक भीषण सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा देर रात उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अचानक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक अंदर ही फंस गया।थाना सरोजनीनगर पुलिस के अनुसार, बीती रात लगभग 12रू30 बजे सूचना मिली कि गंगानगर अमौसी स्थित बिग बॉस्केट के निकट एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक कार सड़क किनारे पेड़ से टकराई हुई मिली और चालक कार के अंदर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरोजनीनगर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक अपनी कार संख्या यूपी 14 ईसी 2220 से हाईवे के रास्ते अनौरा की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन मोड़ के समीप पहुंचा, वह अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान अभिनव (उम्र लगभग 24 वर्ष), पुत्र शिव मोहन निवासी अनौरा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ के रूप में की है।

किसान अब फसल नहीं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है : विनय पटेल

लखनऊ, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान इस समय खाद की किल्लत और फसल बर्बादी की दोहरी मार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चार महीने से किसान खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े हैं, कई जिलों में तो इस अफरा–तफरी में किसानों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन सरकार बेपरवाह बनी हुई है। अब जब गेहूं की बुवाई का समय शुरू हो गया है, तब भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।विनय पटेल ने कहा कि हाल की बारिश और आंधी से पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। झांसी, हमीरपुर और महोबा से किसानों की आत्महत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार केवल मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा, "किसान अब फसल नहीं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।"उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कराकर किसानों को ६20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे, जैसा कि पंजाब सरकार ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याएं यहीं खत्म नहीं हो रहीं कृ धान की फसल तैयार है लेकिन सरकारी क्रय केंद्र बंद पड़े हैं। किसान अपने घरों पर 100 से 200 क्विंटल धान रखे हैं, मगर उन्हें 2369 के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय मजबूरी में ६1600 से 1700 प्रति क्विंटल की दर से बेचना पड़ रहा है।विनय पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों को बिचौलियों के हाथों लुटवा रही हैं ।

प्रताप मार्केट व्यापार मंडल एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न, व्यापारियों ने एकता और सेवा का लिया संकल्प

लखनऊ, (संवाददाता)। दिन सोमवार को लखनऊ व्यापार मंडल की इकाई प्रताप मार्केट व्यापार मंडल एसोसिएशन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल और युवा सशक्त महामंत्री सुमित गुप्ता की मौजूदगी ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया। इसके अलावा राकेश छाबड़ा, जितेंद्र सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी भव्य बना दिया।कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अमरनाथ मिश्र ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित टीम में अध्यक्ष विजय कुमार, वरिष्ठ महामंत्री अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गजेन्द्र पाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकरण अरोड़ा, उपाध्यक्ष अवतार सिंह, रविन्द्र पाल सिंह, बलवीर सिंह अरोड़ा, भूपेन्द्र सिंह सलूजा और राजीव गुप्ता शामिल रहे। वरिष्ठ मंत्री के रूप में अनिल गुलानी, मंत्री के रूप में सुरेश खत्री, प्रमोद अग्रवाल, सौरभ राजवानी और तरन बलजीत सिंह ने पद ग्रहण किया। संगठन मंत्री की जिम्मेदारी राजकुमार अग्रवाल को दी गई जबकि प्रचार मंत्री का दायित्व शालू भाई को सौंपा गया।समारोह के बाद अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि

व्यापार मंडल एक ऐसा सशक्त मंच है जो व्यापारियों की समस्याओं और सुझावों को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करता है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर संगठन को और अधिक मजबूत बनाएं तथा व्यापारी हितों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं।चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि संगठन की असली ताकत उसकी एकता और अनुशासन में है।

संक्षिप्त खबरें

महापौर सुषमा खर्कवाल ने सुनीं नागरिकों की समस्याए

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए दो सौ से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याएं महापौर सुषमा खर्कवाल के समक्ष रखीं। नागरिकों ने मुख्य रूप से साफ–सफाई, जलभराव, मार्ग प्रकाश, सीवर लाइन, नाली निर्माण, संपत्ति कर तथा अतिक्रमण जैसी जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराईं।महापौर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी को जनता से सीधे संवाद स्थापित करते हुए संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।जनता दरबार के दौरान कई शिकायतों का निस्तारण वहीं पर कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों को आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित जोनों को प्रेषित किया गया। महापौर ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए जनता दरबार नियमित रूप से सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग अपनी समस्याएं सीधे नगर निगम प्रशासन के समक्ष रख सकें।कार्यक्रम के दौरान पार्षदगणों और गणमान्य नागरिकों ने भी महापौर से शिष्टाचार भेंट की तथा शहर के विकास, सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय : अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चार विशाल चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी मनोज यादव, सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ओसामा साहब, महराजगंज विधानसभा क्षेत्र में विशाल कुमार जायसवाल और कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र में अजीत सिंह के समर्थन में जनता से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की।अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सफाया होना तय है, क्योंकि जनता अब भ्रष्टाचार, झूठ और लूट के बंडलराज से मुक्ति चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बजट की लूट कर बिहार का पैसा बाहर भेजती रही है, जबकि महागठबंधन उस लूट को रोककर बिहार का पैसा बिहार के विकास में लगाएगा।उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान झूठ और भ्रष्टाचार से है। किसानों और नौजवानों से झूठे वादे किए गए, पर पूरा कोई नहीं हुआ। जब तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री थे, तब युवाओं को नौकरियां मिल रही थीं और विकास की नई लहर उठी थी। भाजपा को यह रास नहीं आया और उसने साजिश कर सरकार गिरा दी। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता भाजपा को जवाब देगी, क्योंकि बिहार में बदलाव की बयार चल चुकी है।अखिलेश यादव ने कहा कि नया बिहार बनेगा, जहां हर घर में नौकरी और खुशहाली होगी। तेजस्वी यादव हर परिवार को रोजगार देंगे, माताओं–बहनों को 2500 रुपये प्रतिमाह, गैस सिलेंडर 500 रुपये में और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता - मंत्री ए.के. शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने सोमवार को अपने लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई करते हुए बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें मंत्री के समक्ष रखीं, जिनमें प्रमुख रूप से विद्युत आपूर्ति, बिल सुधार, ट्रांसफार्मर परिवर्तन, सड़क निर्माण, जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था, पार्कों के रखरखाव और नगर निगम सेवाओं से संबंधित मुद्दे शामिल थे।मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जनपद सुल्तानपुर से आए एक फरियादी की शिकायत पर मंत्री शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल से फोन पर बात की और समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत बिना निस्तारण के लंबित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जनता की सुविधा ही सरकार की जिम्मेदारी है।जनसुनवाई के दौरान मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और प्रत्येक मामले की अद्यतन स्थिति कार्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदानी स्तर पर नियमित भ्रमण करें और जनता की समस्याओं की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करें।मंत्री शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता और शासन के बीच संवाद और विश्वास का मजबूत माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका समाधान व्यावहारिक और स्थायी रूप में किया जाए।इस अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम प्रतिनिधि तथा संबंधित अनुभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।

होटल में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता जो जनपद बाराबंकी की निवासी है, अपने रिश्ते के जीजा के यहां खुर्दही बाजार थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में रह रही थी। बताया गया कि वह कल रात परिवार वालों से नाराज होकर घर से अपना सामान लेकर निकल गई थी। इसी दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात मनोज साहू नामक युवक से हुई, जो कि कनकहा से म्यूजिक प्रोग्राम करके लौट रहा था।दोनों ने कुछ समय बातचीत के बाद एक होटल में ठहरने का निर्णय लिया। वहीं, पीड़िता ने बाद में आरोप लगाया कि आरोपी मनोज साहू ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मनोज साहू को हिरासत में ले लिया और उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं हों बेहतर, भूसा–साइलेज टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए – धर्मपाल सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि भूसा और साइलेज की टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमानुसार सम्पन्न कराई जाए। जहां कहीं भी टेंडर दरों में भिन्नता या अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो, वहां जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी गोआश्रय स्थलों में अनुमन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हों और भरण–पोषण मद में एक माह की अग्रिम धनराशि समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि गोवंश के पालन–पोषण में किसी प्रकार की कमी न रहे।मंत्री ने कहा कि गोशालाओं में चारा, भूसा, पानी, औषधियों और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हर समय बनी रहनी चाहिए। गोआश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास किए जाएं और इस दिशा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जाए। किसानों और पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर भी विशेष बल दिया गया, ताकि वे पशुपालन के क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें।धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवस्थापना कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित बड़े गोआश्रय स्थलों की भूमि को पीपीपी मॉडल पर गो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाएं तलाशने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए।मंत्री ने आगे कहा कि अभियान चलाकर 15 दिसम्बर तक खेतों से पराली उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी गोआश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पशुचिकित्साधिकारी नियमित रूप से गोशालाओं का निरीक्षण करें। साथ ही, राजमार्गों और प्रमुख स्थलों पर विचरने वाले गोवंश को रेडियम बेल्ट पहनाने के निर्देश भी दिए, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण और संवर्धन राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा के दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाए और समिति के सदस्यों को कम से कम दो पशु पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसानों और पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे आधुनिक तकनीक और योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक गांव में दुग्ध समिति गठन का कार्य तेजी से पूरा किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।मंत्री ने कहा कि पराग डेयरी के उत्पादों की गुणवत्ता आज भी उत्कृष्ट और पौष्टिक है, इसलिए उनकी मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। बेहतर विपणन रणनीति के माध्यम से पराग उत्पादों को अधिक लोकप्रिय बनाते हुए उनकी सर्वसुलभता सुनिश्चित की जाए, ताकि यह ब्रांड फिर से उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन सके।बैठक में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पराली संग्रहण अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जाए, साइलेज निर्माताओं से टेंडर पर चर्चा कर मानक दिशा–निर्देश तैयार किए जाएं और पराली का उपयोग गौशालाओं में बिछावन के साथ–साथ कुट्टी बनाकर चारे के रूप में किया जाए। साथ ही, हरा चारा क्रय, नैपियर प्लांटेशन और गोशालाओं में पराग पशु आहार की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।बैठक में दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव, पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ. योगेन्द्र पवार, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉ. मेमपाल सिंह, यूपीएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी.के. सिंह, अपर निदेशक डॉ. संगीता तिवारी तथा संयुक्त निदेशक डॉ. पी.के. सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिए विशेष काउंसिलिंग का पाँचवाँ चरण 4 से 11 नवम्बर तक

लखनऊ, (संवाददाता)। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्मा) पाठ्यक्रम के लिए विशेष काउंसिलिंग का पाँचवाँ चरण प्रारंभ किया जा रहा है। परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि यह ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया 4 नवम्बर से 11 नवम्बर 2025 तक आयोजित होगी। परिषद ने पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय–सीमा का पालन करते हुए अपने लॉगिन के माध्यम से अधिक से अधिक संस्थाओं का चयन करें और निर्धारित तिथि के भीतर काउंसिलिंग में प्रतिभाग सुनिश्चित करें। यह विशेष चरण न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों में विशेष कोटे की सीटों पर भी यह प्रक्रिया लागू रहेगी।सचिव ने बताया कि पाँचवें चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों को अपनी सीट स्वतः फ्रीज करनी होगी तथा निर्धारित अवधि में काउंसिलिंग शुल्क और सुरक्षा धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से परिषद की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्रममबनच.कउपेपवदे.दपब.पद पर उपलब्ध दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और किसी भी सहायता के लिए परिषद कार्यालय के दूरभाष 0522–2630106, 2630695, 2630667, 2636589 पर संपर्क करने की अपील की।उन्होंने बताया कि इस विशेष चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत चॉइस फिलिंग 4 नवम्बर से 6 नवम्बर तक की जाएगी, जिसके बाद 7 नवम्बर को सीट आवंटन किया जाएगा। इसके उपरांत अभ्यर्थियों को 8 नवम्बर से 10 नवम्बर के बीच सुरक्षा शुल्क जमा करने और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। सीट वापसी की अंतिम तिथि 10 नवम्बर निर्धारित की गई है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय शोध का परचम: डॉ. अनुज सिंह का शोध आर्टिकल प्रतिष्ठित BMC जर्नल में प्रकाशित

देश की उपासना
धनन्जय विश्वकर्मा

जौनपुर, उत्तर प्रदेश – भारतीय चिकित्सा शिक्षा जगत के लिए गर्व का क्षण तब आया जब उमा नाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनुज सिंह का महत्वपूर्ण शोध आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित BMC Journal में प्रकाशित हुआ। यह उपलब्धि न केवल संस्थान, बल्कि पूरे देश के लिए सम्मान का विषय है। डॉ. अनुज सिंह ने बताया कि यह शोध । चिकित्सा शिक्षा को और अधिक सरल, प्रभावी व छात्र–केंद्रित बनाने को समर्पित था। उनका उद्देश्य मेडिकल छात्रों और फैकल्टी के लिए सीखने की प्रक्रिया को बेहतर, रोचक और टिकाऊ बनाना था। यह अध्ययन भारत के पाँच प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों। प्रयागराज,

रायपुर, उदयपुर, मुंबई और भोपालकृ में संचालित किया गया। शोध का उद्देश्य इंटीग्रेटेड वीडियो–आधारित शिक्षण पद्धति और पारंपरिक डायडैक्टिक लेक्चर के बीच प्रभावशीलता की तुलना करना था। अध्ययन में पाया गया कि इंटीग्रेटेड वीडियो–आधारित शिक्षण पारंपरिक डायडैक्टिक लेक्चर की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। यह पद्धति मल्टी–सेंसरी एंगेजमेंट को बढ़ाती है, जिससे छात्रों में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है तथा कौशल–विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इसने जटिल विषयवस्तु को सरल, आकर्षक और याद रखने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. सिंह का मानना है कि उनका शोध भविष्य में भारतीय मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में डिजिटलीकृत, एकीकृत और छात्र–उन्मुख शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे न केवल छात्रों का सीखने का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि फैकल्टी भी अधिक प्रभावी, आकर्षक और वैज्ञानिक ढंग से पढ़ा सकेंगे। डॉ. सिंह ने कहा कि यह शोध मेडिकल एजुकेशन में नई दिशा प्रदान करेगा और भविष्य में मेडिकल पाठ्यक्रम की कठिन अवधारणाओं को सरल व अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने की संभावनाएँ खोलेगा। डॉ. सिंह की यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त उपलब्धि न केवल सफलता है, बल्कि यह भारतीय चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम भी है। उनका यह शोध आगामी वर्षों में मेडिकल शिक्षण–पद्धतियों में नए मानक स्थापित कर सकता है और देशभर के मेडिकल शिक्षकों तथा नीति–निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अपनी उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अनुज सिंह ने संस्थान के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से धन्यवाद दिया ।

'माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ के प्रधानाचार्य अनिल वर्मा का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में'

लखनऊ 5 नवम्बर 2025 माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ के प्रधानाचार्य अनिल वर्मा का चयन भारतीय एथलेटिक्स टीम में हुआ है

संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल कार्यालय के मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ दिनेश कुमार ने बताया कि 23वीं इंटरनेशनल एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चौंपियनशिप– 2025 का आयोजन जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, तमिलनाडु में पांच नवम्बर से नौ नवम्बर तक किया जा रहा है,जिसमें 25 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं घ्डॉ दिनेश कुमार ने बताया कि भारत की तरफ अनिल वर्मा ऊंची कूद,भाला फेंक,में प्रतिभाग करेंगे,इस प्रतियोगिता में सभी विभागों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ से अनिल वर्मा का चयन हुआ है विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ दिनेश कुमार ने बताया कि राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल वर्मा का इंटरनेशनल एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चौंपियनशिप–2025 में चयन

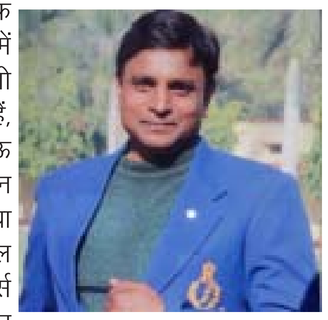

ने लखनऊ जनपद,व मण्डल के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरान्वित किया है घ्अनिल वर्मा ने बताया कि दृढ़ इच्छा शक्ति ,लगन व समय समय पर विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ दिनेश कुमार द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ही उनकी सफलता का मूलमन्त्र रहा है– 'डॉ दिनेश कुमार,मण्डलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी, लखनऊ मण्डल'

संक्षिप्त खबरें

एस.के.डी. एकेडमी में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई गुरुनानक जयंती

लखनऊ (प्रत्यूष पाण्डेय)

एस.के.डी. एकेडमी में गुरुनानक जयंती का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ सभी शाखाओं में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सुरम्य 'शबद कीर्तन' से हुई, जिससे पूरा परिसर गुरु नानक देव जी के दिव्य उपदेशों और आध्यात्मिक ऊर्जा से गुंजायमान हो उठा। विद्यार्थियों ने भाषण, भजन और लघु नाटिका के माध्यम से गुरु नानक देव जी के सत्य, विनम्रता और मानव सेवा के संदेश को प्रस्तुत किया। इस पावन अवसर पर श्री मनीष सिंह, निदेशक, एस.के.डी. ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएँ और आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि। "गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ हमें सत्यनिष्ठा, दया और निःस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाती हैं। उनका समता

और मानवता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें एक बेहतर, करुणामय समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।" कार्यक्रम का समापन सर्वजन की शांति और समृद्धि की प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें सभी ने सौहार्द और एकता की भावना के साथ भाग लिया कृ जिससे गुरुपर्व का वास्तविक संदेश साकार हुआ।

मोटे अनाज के सेवन से सुधरेगी नौनिहालों की सेहत

भदोही, (संवाददाता)। सब कुछ ठीक रहा तो आगामी शिक्षा सत्र से जिले के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले एक लाख 40 हजार बच्चों को एमडीएम में मोटा अनाज (मिलेट्स) मिलेगा। इससे उनकी सेहत बेहतर होगी। करीब एक साल पूर्व महानिदेशक शिक्षा का पत्र आया था, जिसे प्रभावी बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जिले में कुल 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित होते हैं। इनमें एक लाख 40 हजार बच्चे पढ़ते हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक दिवस बच्चों को अलग–अलग मेन्यू के आधार पर भोजन मिलता है। एक साल पूर्व महानिदेशक ने पत्र भेजकर एमडीएम में सप्ताह के एक दिन मोटे अनाज के बने व्यंजन बच्चों को देने का निर्देश दिया था। यह व्यवस्था अभी तक जिले में शुरू नहीं हो सकी है। अब धीरे–धीरे प्रशासन इसको लेकर हरकत में आ गया है। पिछले दिनों डीएम की बैठक में व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इसमें मोटे अनाज का उत्पादन करने वाली एफपीओ का चयन करने पर बल दिया गया। अब कृषि और शिक्षा विभाग की तरफ से इसे लेकर तैयारी की जा रही है। इसके सेवन से बच्चों की सेहत और भी बेहतर होगी। उप निदेशक कृषि डॉ. अश्वनी सिंह ने बताया कि मोटे अनाज को स्कूलों में शामिल करने की व्यवस्था अभी पाइपलाइन में है। उच्चाधिकारियों के दिशा–निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी ने बताया कि स्कूलों में एमडीएम के साथ मोटे अनाज देने की तैयारी की जा रही है।

कार्तिक पूर्णिमा/गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर नर्मदा तीर्थ स्थल पर खिचड़ी–तहरी(प्रसाद)भोज का आयोजन

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

कार्तिक पूर्णिमाध्गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर नर्मदा तीर्थ स्थल शाहाबाद पिछले चार दशकों से खिचड़ी–तहरी(प्रसाद)भोज के आयोजन के अवसर पर वक्ताओं ने गुरुनानक देव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हम सब यहाँ भारत महान संत, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन "गुरुपर्व" या "प्रकाश पर्व" के नाम से पूरे भारत और दुनिया भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने समाज में फैली असमानता, छुआछूत, अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संदेश था "एक ओंकार सतनाम" कृ अर्थात, ईश्वर एक है और सबमें विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि सभी धर्मों और जातियों का मूल एक ही है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की सेवा करे।गुरु नानक देव जी का जीवन सादगी, प्रेम और करुणा से भरा था। वे सिखाते थे कि इंसान को भेदभाव छोड़कर प्रेम, समानता और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज के समय में, जब समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ और भी प्रासंगिक हैं। हमें उनके बताए मार्ग पर चलकर एक शांतिपूर्ण, समान और प्रेमपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के संस्थापक स्मृति शेष निशीकांत गुप्ता– स्मृति शेष श्री राम स्वरूप अरोड़ा जी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आयोजन शुभारंभ समाजसेवी नलिन गुप्ता(डब्ल्यू) ने सभी सहयोगी सुशील शर्मा, बसंत गुप्ता, राजीव गुप्ता, राम जी तिवारी, राम राज्य सिंह सभासद रमाकांत मौर्य, अतुल मिश्रा,शानू गुप्ता,सुवीन गुप्ता, गोपाल जी, वैभव मिश्रा, सतीश चन्द्र, लालू कश्यप, राकेश राजपूत ने प्रथम साधुओं एवं कन्याओं को प्रसाद एवं दक्षिणा देकर मेला में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार शाहाबाद की गरिमामई उपस्थिति बनी रही।

भागवत कथा श्रवण मात्र से पाप से मिलती है मुक्ति- आचार्य रविकांत शास्त्र

अयोध्या।जाना बाजार स्थित तिवारीपुर पछियाना में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में प्रवाचक आचार्य रविकांत शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा श्रवण मात्र से पाप से मुक्ति मिलती।कहा कि जिस स्थान पर कथा होती है वहां भगवान विराजमान होते हैं।भगवन नाम के जाप से सारे विपत्ति नाश हो जाते हैं। इस जगत में भगवत कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य को समाज में अच्छे काम करना चाहिए। इसलिए सभी को अच्छे कर्मो के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मार्ग दमन का है तो दूसरा उदारीकरण का। दोनों ही मार्गो में अधोगामी वृत्तियां निषेध हैं। जैसे कि गोकर्ण ने कथा कही, किन्तु उसके दुराचारी भाई धुंधकारी ने मनोयोग से उसे सुना तो मोक्ष प्राप्त हो गया। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि इसका जितना भी पान किया जाए आत्मा तृप्ति नहीं होती है। भागवत कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य जाग जाए ध्रुव चरित्र और सती चरित्र का प्रसंग सुनाया। ध्रुव चरित्र के प्रसंग में भगवान ने भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर अटल पदवी देने का वर्णन किया।

कहा कि भगवान शिव की अनुमति लिए बिना उमा अपने पिता दक्ष के यहां यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए जाने से कुपित होकर सती ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर शरीर त्याग दिया। इससे नाराज शिव के गणों ने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसलिए जहां सम्मान न मिले वहां कदापि नही जाना चाहिए। कथा में आयोजक डॉ अम्बिकेश त्रिपाठी,विमलेश त्रिपाठी,करुणेश त्रिपाठी, परूइया आश्रम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर परेश पाण्डेय और बी एन के बी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर की प्राचार्या प्रोफेसर सुचिता पाण्डेय, श्रेयश त्रिपाठी , अथर्व वेद त्रिपाठी , रामकृपाल तिवारी देवता दिन तिवारी रवींद्रनाथ तिवारी पारस त्रिपाठी सोभनाथ त्रिपाठी सहित श्रोतागण मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

10 महीने से खोदकर छोड़ी सड़क, व्यापार चौपट

भदोही, (संवाददाता)। वाराणसी से मछलीशहर तक निर्माणाधीन हाईवे में बरती जा रही उदासीनता का खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्य बाजार में तीन जगह 10 महीने से सड़क के किनारे खोदकर छोड़े गए गड्ढों से त्योहारी सीजन में व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है। जगह–जगह सड़क, पुलिया व नाली के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ देने वाली कार्यदायी संस्था कोई खबर नहीं ले रही है। इसे लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। कंधिया फाटक से इंदिरा मिल चौराहे तक हाईवे निर्माण कार्य में शुरू से उदासीनता बरती जा रही है। लगभग दो वर्ष हो चुके कार्य को शुरू हुए लेकिन किसी स्थान पर भी कार्य पूरा नहीं दिख रहा है। जगह–जगह सड़क के गड्ढे, नाली के लिए खोदे गए गड्ढे, अधूरी सड़क, डिवाइडर और पुलिया राहगीरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इससे बाजार की रौनक फीकी हो गई है। भदोही–वाराणसी मार्ग पर सबसे बड़े बाजार में शुमार चौरी की हालत तो हाईवे निर्माण में लापरवाही से खराब हो गई है। चकिया तिराहे और उसके दोनों तरफ मछरहट्टा, कोल्हड़ हनुमान मंदिर के पास सड़क के लिए गड्ढे खोदकर छोड़े हुए 10 महीने से अधिक समय बीत गए हैं। कई स्थानों पर नालियां व डिवाइडर भी अधूरे हैं। इससे मनमाने ढंग से वाहनों का आवागमन हो रहा है।

गंगा में पानी ज्यादा, एक महीने विलंब से शुरू होंगे पीपा पुल

भदोही, (संवाददाता)। प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो चुके हैं लेकिन गंगा में बनने वाले पीपा पुलों का निर्माण अधर में है। गंगा में अधिक पानी होने के कारण पीपा पुलों के निर्माण में एक से डेढ़ माह का समय लग सकता है। पुलों को खोलने का समय 10 से 15 जून तय है। वहीं निर्माण के लिए दशमी के दिन पूजा पाठ का समय नियत है। जिले के तीन गंगा घाटों पर पीपा पुल का निर्माण होता है। इन पीपा पुलों के माध्यम से हर दिन 70 से 80 लोग गंगा आरपार की सुगम यात्रा करते हैं। तीनों पीपा रामपुर, सीतामढ़ी और धनतुलसी गंगा में पीपा पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग करता है। इनमें रामपुर और धनतुलसी पीपा पुल पीडब्ल्यूडी भदोही और सीतामढ़ी–मिश्रपुर पीपा पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी मिर्जापुर कराता है। तीनों पीपा पुल काफी महत्वपूर्ण है। इन पीपा पुलों के बन जाने से गंगा पार जाने में लगभग 100 किमी की दूरी कम हो जाती है। खास तौर पर लगन के सीजन में जिले के तीनों पीपा पुलों की उपयोगिता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। खास तौर पर जिस दिन लगन होता है। उस दिन गंगा आर पार आने जाने में गाड़ियों का तांता लग जाता है। सहालग का दौर शुरू होने के बाद भी अब तक गंगा में पानी में कमी न आने से पीपा पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। जिस तरह गंगा का जलस्तर बना हुआ है, उससे अब भी एक माह विलंब से पीपा पुल निर्माण होने की आशंका है। ऐसे में गंगा इस पार से उस पार आने–जाने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा नौकाओं का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। जिले के रामपुर, धनतुलसी और सीतामढ़ी में बनने वाली पीपा पुल से भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज के मांडा क्षेत्र की दूरी कम हो जाती है। पीपापुल के बिना अगर मांडा जाना है तो भदोही से हंडिया या सैदाबाद जाना पड़ेगा।

शारदा पार हाथियों ने झोंपड़ियां तोड़ीं, महिला ने भागकर बचाई जान

पीलीभीत, (संवाददाता)। शारदा नदी के पार नेपाल के जंगली हाथियों का उत्पात बना है। शनिवार रात झोंपड़ी में सो रहे ग्रामीण को कुचलने की घटना के बाद रविवार रात फिर हाथियों ने ढकिया, गुन्हान क्षेत्र में दस्तक देकर जमकर दहशत फैलाई। करीब सात झोंपड़ियां तहस–नहस कर दीं। एक झोपड़ी में सो रही महिला ने भागकर जान बचाई। ग्रामीणों के अनुसार करीब पांच एकड़ दायरे में गन्ने और सोयाबीन की फसल को हाथियों ने रौंद दिया। माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी के पार नेपाली हाथियों की पिछले कुछ दिनों से दहशत है। नेपाल की शुक्ला फांटा सेंचुरी से आने वाले ये हाथी रात को ढकिया ताल्लुके महाराजपुर, गुन्हान और गोरख डिब्बी क्षेत्र की सीमा में पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं। फसलों को रौंदने के साथ किसानों की

झोंपड़ियां तोड़ रहे हैं। शनिवार रात ढकिया ताल्लुके महाराजपुर में पहुंचे करीब 20 से अधिक हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने झोंपड़ी में घुसकर वहां सो रहे ग्रामीण पुन्नो को रौंदकर मार दिया था। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत थी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने निगरानी शुरू की थी। इधर निगरानी के दावों के बीच रविवार रात फिर हाथी शारदा पार रमनगरा नंबर चार, ढकिया और गुन्हान क्षेत्र में पहुंच गए। रमनगरा नंबर चार में झुंड के साथ पहुंचा एक हाथी ग्रामीण सुरेंद्र के झोपड़ीनुमा घर में पहुंच गया। घर में सुरेंद्र की पत्नी भागमनी देवी अकेली सो रही थी। चिंघाड़ने की आवाज पर वह जाग गई और जान बचाने को दौड़ लगा दी। आसपास के ग्रामीण एकत्र हो गए। हाथियों को बमुश्किल खदेड़ा।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी गाड़ियों पर अब टैक्सी परमिट अनिवार्य, परिवहन विभाग ने जारी किया पत्र

पीलीभीत, (संवाददाता)। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की जंगल सफारी में दौड़ती गाड़ियों पर भी टैक्सी परमिट का नियम लागू होगा। पर्यटन के नाम पर सफारी चलाने वाले वाहन अब परिवहन विभाग के दायरे में आएंगे। विभाग ने इस संबंध में पीटीआर प्रशासन को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि सफारी में प्रयोग होने वाले सभी वाहनों को टैक्सी परमिट लेना होगा। गौरतलब है कि पीटीआर की स्थापना के बाद पर्यटकों को जंगल सैर कराने के लिए सफारी वाहनों की व्यवस्था की गई थी। ये गाड़ियां अब तक गैर–व्यावसायिक श्रेणी में आती थीं, लेकिन परिवहन विभाग ने अब इन्हें टैक्सी श्रेणी में शामिल कर दिया है। एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने इस संबंध में पीटीआर को पत्र लिखा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों और सफारी वाहनों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब वीकडेज और वीकेंड पर अलग–अलग शुल्क लिया जाएगा। सैलानियों को पहले महोफ एक नंबर से बुकिंग करने में 2500 जिप्सी व 100 रुपये प्रति सैलानी की दर से रुपये जमा करने पड़ते थे। अब यह रेट सोमवार से शुक्रवार तक 2500 रुपये और प्रति व्यक्ति 100 से बढ़कर 120 कर दिया गया है। जबकि शनिवार और रविवार को यह रेट वाहन खर्च के अलावा 150 रुपये प्रति सैलानी के

हिसाब से जमा करना होगा। इसी तरह मुस्तफाबाद के बुकिंग काउटंर से पहले जिप्सी वाहन के 2000 रुपये और प्रति सैलानी 100 रुपये जमा करने पड़ते थे। अब सोमवार से शुक्रवार तक प्रति सैलानी का खर्च 100 से बढ़कर 120 कर दिया गया है। जबकि शनिवार और रविवार को यह रेट प्रति व्यक्ति 150 रुपये जमा करना होगा। दोनों जगाहों पर जिप्सी और बड़े जीनान वाहन के रेट में पांच सौ रुपये का अंतर है। जंगल सफारी के समय में आधे घंटे की बढ़ोतरी भी की गी है। सुबह की पाली में जहां पहले तीन घंटे का समय मिलता था, वहीं अब सैलानी साढ़े तीन घंटे तक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। शाम की पाली पूर्ववत तीन घंटे की ही रहेगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रस्तावित बजट पर भी चर्चा की गई जिसमें बाघ संरक्षण, ईको विकास, अनुसंधान और ईको टूरिज्म से जुड़े कार्यों पर व्यय का प्रस्ताव रखा। साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व की एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी सहमति बनी।

गंगा में पानी ज्यादा, एक महीने विलंब से शुरू होंगे पीपा पुल

भदोही, (संवाददाता)। प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो चुके हैं लेकिन गंगा में बनने वाले पीपा पुलों का निर्माण अधर में है। गंगा में अधिक पानी होने के कारण पीपा पुलों के निर्माण में एक से डेढ़ माह का समय लग सकता है। पुलों को खोलने का समय 10 से 15 जून तय है। वहीं निर्माण के लिए दशमी के दिन पूजा पाठ का समय नियत है। जिले के तीन गंगा घाटों पर पीपा पुल का निर्माण होता है। इन पीपा पुलों के माध्यम से हर दिन 70 से 80 लोग गंगा आरपार की सुगम यात्रा करते हैं। तीनों पीपा रामपुर, सीतामढ़ी और धनतुलसी गंगा में पीपा पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग करता है। इनमें रामपुर और धनतुलसी पीपा पुल पीडब्ल्यूडी भदोही और सीतामढ़ी–मिश्रपुर पीपा पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी मिर्जापुर कराता है। तीनों पीपा पुल काफी महत्वपूर्ण है। इन पीपा पुलों के बन जाने से गंगा पार जाने में लगभग 100 किमी की दूरी कम हो जाती है। खास तौर पर लगन के सीजन में जिले के तीनों पीपा पुलों की उपयोगिता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। खास तौर पर जिस दिन लगन होता है। उस दिन गंगा आर पार आने जाने में गाड़ियों का तांता लग जाता है। सहालग का दौर शुरू होने के बाद भी अब तक गंगा में पानी में कमी न आने से पीपा पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। जिस तरह गंगा का जलस्तर बना हुआ है, उससे अब भी एक माह विलंब से पीपा पुल निर्माण होने की आशंका है। ऐसे में गंगा इस पार से उस पार आने–जाने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विभाग द्वारा नौकाओं का संचालन तो किया जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। जिले के रामपुर, धनतुलसी और सीतामढ़ी में बनने वाली पीपा पुल से भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज के मांडा क्षेत्र की दूरी कम हो जाती है।

उग्रसेन के राज्याभिषेक के साथ देवोत्थानी मेले का समापन

सीतापुर, (संवाददाता)। उग्रसेन राज्याभिषेक के मंचन के साथ कस्बे में चल रहे दो दिवसीय देवोत्थानी एकादशी मेले का सोमवार को समापन हो गया। लीला मंचन में कलाकारों के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसमें दिखाया गया कि उग्रसेन मथुरा के राजा थे। कंस द्वारा राजा उग्रसेन को छल से बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता है। इसके बाद मंचन में दिखाया गया कि देवकी की आठवीं संतान कंस का काल होने की आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था। दुष्ट मामा कंस को हराने के बाद श्रीकृष्ण ने न सिर्फ मथुरा को शांति प्रदान की बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना भी की। कंस के शासन में कैद और अपमानित किए गए महाराज उग्रसेन को उनके सिंहासन पर दोबारा आसीन किया गया। ढोल–नगाड़ों की गूंज, पुष्पवृष्टि, वेद मंत्रों का उच्चारण और ब्राह्मणों द्वारा शुभाशीष के बीच श्रीकृष्ण ने महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर मथुरावासियों ने उल्लास और कृतज्ञता के साथ राजा उग्रसेन का स्वागत किया। राजा उग्रसेन ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनका शासन धर्म, दया, न्याय और कल्याण का होगा। श्रीकृष्ण ने भी प्रण किया कि वे सदैव धर्म की रक्षा करेंगे और राष्ट्र व प्रजा के हित में कार्य करेंगे। इस मौके पर संत नीरज दास खाकी, दिनेश चंद्र गुप्ता, राजबहादुर सिंह, नैमिष गुप्ता, चंद्र किशोर शर्मा, संदीप शर्मा, गोपीनाथ गुप्ता, अनिल वर्मा, आकाश शर्मा, सूरज आदि मौजूद रहे।

19 ब्लॉकों में बनेंगे फायर स्टेशन, आरक्षित होगी जमीन

सीतापुर, (संवाददाता)। जिले को जल्द 19 नए फायर स्टेशनों की सौगात मिलेगी। यह सभी फायर स्टेशन 19 ब्लॉकों में प्रस्तावित है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने सभी उपजिलाधिकारियों को फायर स्टेशनों के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए पत्र लिखा है। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि यह फायर स्टेशन एलिया, बेहटा, बिसवां, गोंदलामऊ, हरगांव, कसमंडा, खैराबाद, लहरपुर, मछरेहटा, महमूदाबाद, महोली, मिश्रिख, पहला, परसेंडी, पिसावां, रामपुर मथुरा, सकरन, सिधौली और रेउसा में बनना प्रस्तावित हैं। प्रत्येक फायर स्टेशन के लिए 4184 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। यह सभी अग्निशमन केंद्र श्रेणी सी के होंगे। यह केंद्र तहसील स्तर पर संचालित फायर स्टेशन से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक स्तर पर स्थापित होंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।